P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-7* (Part-2) March- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

छत्तीसगढ़ के शासकीय व अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के प्राचार्यो के दृष्टिकोण से संपूर्ण गुणवत्ता मूल्यांकन : प्रशिक्षण के उददेश्य एवं अवधि के सदंर्भ में एक अध्ययन

सत्यप्रकाश यादव
शोधार्थी,
शिक्षा शास्त्र विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत

प्रकृति जेम्स
सहायक प्राध्यापक
शिक्षा शास्त्र विभाग,
पं. सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त)
विश्वविद्यालय,
छत्तीसगढ़, बिलासपुर, भारत

सारांश

वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी है, आज उसे जहां स्वयं विद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय–विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1996 के अनुसार शिक्षा के चार स्तम्भ– ज्ञान के लिए सीखना, स्व–अस्तित्व के लिए सीखना, कार्य के लिए सीखना एवं सहअस्तित्व के लिए सीखना है, इन चार स्तम्भों का आधार शिक्षक है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए मानक के अनुसार सुविधा सम्पन्न उच्च कोटि शासकीय– अशासकीय की शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें हो।

मुख्य शब्द : NCERT, NUEPA, डाईट, गुणवत्ता।

प्रस्तावना

शिक्षा की दृष्टि से ''प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण'', ''गुणवत्तापूर्ण सभी के लिए शिक्षा'', आदि राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख लक्ष्य रहें हैं। इसी क्रम में 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा देना, आज उनका मौलिक अधिकार बन गया है, साथ ही यह लक्ष्य देश का संवैधानिक उत्तरदायित्व भी हो गया है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में हम यह कह सकते हैं शिक्षण जैसे उत्तम कार्य में शिक्षक की भूमिका केन्द्रीय हो गई है। वर्तमान समय में शिक्षक से हमारी अपेक्षाएँ बढ़ गयी है, आज उसे जहां स्वयंविद्यार्थी, समाज, शाला, व्यवसाय इत्यादि के प्रति समर्पित होना है, वहीं विषय–विशेषज्ञ, चिंतक के रूप में भी अपने को साबित करना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1996 के अनुसार शिक्षा के चार स्तम्भ– ज्ञान के लिए सीखना, स्व–अस्तित्व के लिए सीखना, कार्य के लिए सीखना एवं सहअस्तित्व के लिए सीखना है, इन चार स्तम्भों का आधार शिक्षक है। अतः हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं, इन अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु एक कुशल शिक्षक तैयार करना होगा और यह तभी संभव है जब देश में शिक्षक को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए मानक के अनुसार सुविधा सम्पन्न उच्च कोटि शासकीय–अशासकीय की शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें हो। देश के सभी राज्यों में ऐसी संस्थाओं के गठन हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किये जा रहें है।

इसी तारतम्य में स्थानीय एवं जिला स्तर पर प्रारंभिक शालाओं के शिक्षकों को सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण देने तथा सभी प्रकार के उत्तरदायित्व और संसाधन उपलब्ध कराने के लिए शासकीय एवं अशासकीय डी. एल.एड. शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थायें संचालित की गयी है और इनकी संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही हैं। इन संस्थाओ के प्रमुख लक्ष्य निम्नानुसार वर्णित हैं –

1. प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण करना।
2. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सफल बनाने की दृष्टि से अकादमिक तथा अन्य संसाधनों की पूर्ति करना।
3. प्रशिक्षण संस्थाये स्वयं को इतना उन्नत बनायेगी कि उनसे प्रारंभिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके।
4. जिले की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं को विकास की दिशा में आगे बढाने के लिये योजनाओं का निर्माण एवं उनका क्रियान्वयन करना।

5. अध्यापकों को उच्चस्तरीय सेवापूर्व–सेवाकालीन प्रशिक्षण देना।
6. अध्यापक शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया में आस–पास के साधनों का अधिकतम प्रयोग कर सकें ।
7. प्रशिक्षण संस्थाओं में अध्ययन–अध्यापन की सहायक सामग्री का निर्माण करना तथा मूल्यांकन उपकरण निर्मित करना।
8. क्रियात्मक अनुसंधान पर बल देना।
9. दिव्यांगों एवं वंचित वर्ग के बच्चों की समावेशी शिक्षा की व्यवस्था करना ।

उपरोक्त लक्ष्यों को पूरा करने हेतु प्रारम्भिक शालाओं के शिक्षकों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण देने एवं सभी प्रकार के संसाधन हेतु डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाए स्थापित की गयी। डी.एल.एड., अध्यापक शिक्षा का व्यावसायिक पाठ्यक्रम है जिसका उद्देश्य कक्षा आठवीं तक के अध्यापकों को तैयार करना है। डी.एल.एड. पाठ्यक्रम का उद्देश्य समाज की सहभागिता से सामाजिक विषमताओं को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकता को पूर्ण करना है। शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को कार्य करते लम्बा समय बीत गया है अब उनके कार्य प्रणाली, अध्यापकीय व्यवहार, एवं दक्षता का मूल्यांकन का उपयुक्त समय आ चुका है। देश के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में शासकीय एवं अशासकीय शिक्षक–प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो रहे है यह शिक्षक–प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन संस्थानों को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (DPEP) तथा सर्वशिक्षा अभियान जैसे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का आधार मानते हुये, इन्हें सभी प्रकार की अधुनातन सुविधायें एवं तकनीक उपलब्ध कराने हैं जिसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नयी दिल्ली (NCTE) ने मानक व दिशा निर्देश निर्धारित किये हैं।

साहित्यावलोकन

बनर्जी (1967) ने भारत में प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण पर अध्ययन किया। इनके अध्ययन के निम्न परिणाम थे कि शिक्षक प्रशिक्षण में बहुत सी कमियां थीं। परिवर्तनों और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शिक्षक प्रशिक्षण में आमूल परिवर्तन आवश्यक था। मूल्यांकन व शिक्षण पद्धतियां पुरानी थीं।

मूलैया (1968) ने मध्यप्रदेश में शिक्षक प्रशिक्षण की स्थिति का अध्ययन किया। इस अध्ययन का निष्कर्ष यह प्राप्त हुआ कि मध्य प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय अभावग्रस्त थे। विद्यालयों में संसाधनों की कमी थी। मूल्यांकन और शिक्षण विधि परंपरागत थी। पुरूषों की संख्या महिलाओं की अपेक्षा अधिक थी।

गुप्ता (1980) द्वारा माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण की आवश्यकता पर अध्ययन किया गया। इस अध्ययन के यह परिणाम निकले कि शिक्षक प्रशिक्षकों की शैक्षिक योग्यता एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण में सह संबंध होता है। शिक्षण अनुभवों का प्रशिक्षण कार्य पर प्रभाव पड़ता है। समाजोपयोगी कार्य व्यावसायीकरण सामुदायिक कार्य व शिक्षण पद्धति आदि का ज्ञान देना आवश्यक है।

गुप्ता (1982) द्वारा भारत में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। इस अध्ययन के ये परिणाम प्राप्त हुए कि 61 से 70 के बीच संस्थानों की वृद्धि हुई है। 83 प्रतिशत शिक्षक प्रशिक्षक पुरूष थे। प्रशिक्षक संस्थानों की कार्य प्रणाली प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन प्रणाली परंपरागत थी। ज्यादार गांवों से संबंधित थे। केवल 18 प्रतिशत छात्र एम.एड. उपाधि प्राप्त थे। शारीरिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को महत्व नहीं दिया जाता था। स्थानीय संस्थानों की व्यवस्था से ठीक थी। वाद–विवाद विधि ज्यादा प्रचलित थी।

राय (1982) ने उत्तर प्रदेश तथा गुजरात के शिक्षा महाविद्यालयों और अभ्यास शिक्षण शालाओं (Practice Teaching Schools) से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला है कि :–

1. शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के परिप्रेक्ष्य में अनेकों कमियॉ उजागर हुई हैं। शिक्षा महाविद्यालयों एवं अभ्यास शालाओं के बीच परस्पर सहयोग के अभाव के साथ–साथ यह भी पता चलता है कि शिक्षा महाविद्यालय के प्रशिक्षार्थियों द्वारा अभ्यास शालाओं में जाने से उनके कार्यक्रम, एवं अन्य नियमित गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है।
2. इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि अभ्यास शालाओं एवं शिक्षक– प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रभावशाली सहयोग होना चाहिए।

सिन्हा (1982) ने बिहार में शिक्षक–शिक्षा विषय पर अध्ययन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि –

1. प्राथमिक स्तर पर लगभग 60 प्रतिशत शिक्षक–प्रशिक्षक बी.एड. प्रशिक्षित हैं परन्तु उनका कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया।
2. 70 प्रतिशत महाविद्यालय में स्वयं का भवन नहीं पाया गया और 65 प्रतिशत महाविद्यालयों में दयनीय स्थिति वाले भवन पाये गये।
3. अधिकांश शिक्षा महाविद्यालयों में स्टॉफ, पुस्तकालय, उपकरण तथा प्रयोगशाला अपर्याप्त पाये गये।
4. आधुनिक नवाचारी कार्यक्रमों का समावेश अभी तक शिक्षक–शिक्षा कार्यक्रमों में नहीं हो पाया है।
5. सेवाकालीन प्रशिक्षण न तो प्रभावशाली ढ़ंग से दिये जाते हैं और न ही अध्यापन अभ्यास कार्य कराने में पर्यवेक्षक शिक्षक पर्याप्त ध्यान देते।

अध्ययन का औचित्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (NCERT) राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) तथा डाईट जैसी राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं के द्वारा योजना के क्रियान्वयन, लक्ष्य प्राप्ति तथा उससे अपेक्षाओं पर किये गए राष्ट्र स्तरीय मूल्यांकन निष्कर्ष बहुत अधिक सकारात्मक एवं उत्साहवर्धक नहीं रहे है।

इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ में संचालित डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में मानको के अनुरूप कार्यो का मूल्यांकन करना विशेष शैक्षिक महत्व का होगा क्योंकि

इस शोध अध्ययन के निष्कर्ष के प्रकाश में डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं की वास्तविक स्थितियों का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा और समय रहते ही योजनाबद्ध ढंग से उनकी त्रुटियों को सुधारने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। इस संदर्भ में यह पता लगाना कि छत्तीसगढ़ राज्य की विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सेवारत आचार्य अपने–अपने संस्थाओं कि अपेक्षाओ सुविधाओ, प्रयासो, कियाकलापों, गुणवत्ता आदि से कितना परिचित है उनकी सजगता इस ओर कितनी है, विशेष महत्व का है क्योंकि आचार्यो की ऐसी ही परिकल्पनाओं, अवबोध तथा सजगता पर राज्य में डी.एल. एड. प्रशिक्षण की योजना की सफलता निर्भर करती है। इसलिए एक ऐसा शोध अध्ययन जिससे निम्नलिखित शोध–प्रश्नों के हल ढूंढा जाये , छत्तीसगढ़ राज्य में सृदृढ़ प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था के लिए अत्यंत औचित्यपूर्ण होगा क्योंकि इस नवोदित राज्य में इस प्रकार का अध्ययन अभी तक चरितार्थ नहीं हुआ है। इस सर्वेक्षणात्मक अध्ययन के निष्कर्ष राज्य के लिए दिशा निर्देशक होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध अध्ययन के लिए निम्नांकित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं –

शासकीय एव अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं मे प्रशिक्षण के उद्देश्य एव प्रशिक्षण की अवधि का अध्ययन करना।

अध्ययन की परिकल्पना

प्रस्तुत अध्ययन के उद्देश्यों की जांच हेतु निम्नांकित परिकल्पनायें बनायी गयी हैं –

1. शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं में NCTE के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण के उद्देश्यो को पूरा करने का सकारात्मक प्रयास किया जाता है।
2. शासकीय एव अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण की संस्थाओं मे NCTE के मानक के अनुरूप प्रशिक्षण की निश्चित अवधि मे ही प्रशिक्षण को पूरा करने का सकारात्मक प्रयास किया जाता है।

प्रस्तावित शोध विधि (Research Method)

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णात्मक अध्ययन है जिसमे सर्वेक्षण विधि का उपयोग किया जायेगा।

न्यादर्श (Sample)

न्यादर्श के रूप में शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत प्राचार्य हैं। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में से 16 जिलों में शासकीय डाईट्स एवं दो जिलों में दो बी.टी.आई संचालित हो रहे हैं। इन्हीं जिलो के 18 अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं को यादृच्छिक विधि से चुना गया है ।

अध्ययन के चर

प्रस्तुत अध्ययन में चर एवं उनके स्तर निम्नानुसार है –

स्वतंत्र चर (Independent Variable)

डाईट/डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् नई दिल्ली द्वारा निर्धारित कार्यक्रम एवं मानक प्रस्तुत अध्ययन में स्वतंत्र चर हैं।

आश्रित चर (Dependent Variable)

शासकीय एवं अशासकीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं में सम्पूर्ण गुणवत्ता का मूल्यांकन गुणात्मक सूचक (Indicator) इस अध्ययन के आश्रित चर है जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा वर्णित है, के माध्यम से किया गया है।

उपकरण (Tool)

प्रस्तुत शोध अध्ययन में स्वनिर्मित उपकरण का उपयोग किया गया है।

संस्था के प्राचार्य हेतु साक्षात्कार पत्रक

प्रदत्तों का विश्लेषण

1. डी.एल.एड. प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष रखी गई है, क्या आप इसे उचित मानते हैं ?

हां	नहीं
94.45%	05.55%

94.45 प्रतिशत प्राचार्यो ने प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष उचित माना है जबकि 05.55 प्रतिशत प्राचायों ने इसे अस्वीकार किया है।

2. डी.एल.एड. प्रशिक्षण का शुल्क आपकी दृष्टि से उचित है।

हां	नहीं
77.78%	22.22

77.78 प्रतिशत प्राचार्यो ने डी.एल.एड. का प्रशिक्षण शुल्क को उचित माना है जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचायों ने इसे अस्वीकार किया है।

3. द्विवर्षीय प्रशिक्षण–अवधि के प्रत्येक वर्ष में कुल कार्य दिवस कम से कम 200 दिन का है। क्या इसे आप सुविधाजनक मानते हैं ?

हां	नहीं
94.45%	5.55%

94.45% प्राचार्यो ने प्रशिक्षण अवधि में 200 कार्य दिवस पर को उचित मानते है जबकि 5.55% प्राचार्य इस सुविधाजनक नही मानते हैं।

4. क्या प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य करने का लक्ष्य पूरा होता है ?

हां	नहीं
88.89% (16)	11.11% (2)

88.89% प्राचार्यो ने स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य का लक्ष्य पूरा किया जाता है जबकि 11.11% प्राचार्य इसे नहीं मानते है।

5. क्या छात्राध्यापकों की उपस्थिति प्रायोगिक सहित अकादमिक कार्यो में 80 प्रतिशत तथा स्कूल इन्टर्नशिप में 90 प्रतिशत हो पाती है ?

हां	नहीं
77.78% (14)	22.22% (4)

77.78% प्राचार्यो छात्राध्यापको की उपस्थिति स्वीकारते है जबकि 22.22% प्राचार्य छात्राध्यापको की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं।

6. डी.एल.एड. प्रशिक्षण के नये पाठ्यक्रम को कियान्वयन करके इसके माध्यम से छात्राध्यापकों को पहली कक्षा से आठवीं कक्षा के अध्यापन हेतु क्षमतावान व

नवाचारी विचारों के अध्यापक तैयार करना है क्या आपके मत से इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु नया पाठ्यक्रम सक्षम है ?

हां	नहीं
88.88% (16)	11.12% (4)

डी.एल.एड. के नये पाठ्यक्रम को 88.88% प्राचार्य सक्षम मानते है जबकि 11.12% प्राचार्य इसे सक्षम नही मानते।

7. क्या आपके मत से प्रशिक्षार्थियों की कक्षा समावेशी बनाने में समुदाय का सक्रिय सहयोग मिलता है ?

हां	नहीं
61.11% (11)	38.89 % (7)

61.11% प्राचार्यो ने समुदाय के सक्रिय सहयोग को माना है। 38.89% प्राचार्य समुदाय के सहयोग नही मिलने की बात करते है।

विवेचना

प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं अवधि पर प्राचार्यो के निष्कर्ष से यह कहा जा सकता है कि डी.एल.एड. पाठ्यक्रम की अवधि जो छब्ज् में मानक अनुरूप दो शैक्षणिक अवधि का होगा, उचित है इसे सभी प्राचार्यो ने भी स्वीकार किया है क्योंकि दो वर्ष की अवधि में विद्यार्थियों की सैद्धांतिक कक्षाएं, प्रयोगात्मक कार्य, इन्टर्नशिप जैसे कार्यक्रम को पूरा करना होता है, अतः यह अवधि उचित है। डी.एल.एड. का शुल्क NCTE के अनुरूप राज्य सरकार/संबंधित संबद्धन निकाय द्वारा समय समय निर्धारित की जाती है अतः ज्यादातर प्राचार्यों ने पाठ्यक्रम के शुल्क को भी स्वीकार किया है अधिकतर प्राचार्यो ने भी यह भी स्वीकार किया है कि प्रवेश व परीक्षा की अवधि को छोड़कर भी वर्ष में 200 दिन एवं प्रति सप्ताह 36 घण्टे की अवधि को पूरा कर पाठ्यक्रम को पूर्ण किया जाता है। प्राचार्यो ने इन्टर्नशिप में छात्राध्यापकों की उपस्थिति को गंभीरता से लिया है और छात्राध्यापकों द्वारा 90% उपस्थिति पूर्ण की जाती है NCTE मानक में प्रारंभिक शिक्षा का उद्देश्य समाज की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक और लिंग अंतरो को दूर करते हुए समावेशी स्कूल पर्यावरण में सभी बच्चों की शिक्षा प्राप्त करने की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है प्राचार्यो ने संस्था की गुणवत्ता व पाठ्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने में संस्था, समुदाय, पालक इत्यादि के सहयोग को स्वीकारा है।

डॉ. चक्रवर्ती के अध्ययन के निष्कर्षो के अनुसार डी.एल.एड. पाठ्यक्रम के प्रारंभ में प्रशिक्षार्थियों की अभिवृद्धि, प्रशिक्षण पूरा करने पर प्राप्त अभिवृत्ति में परिवर्तन आना प्रशिक्षण के प्रति अत्यंत सकारात्मक अभिवृत्ति के विकास का संकेत देता है और सुविधा संपन्न प्रशिक्षण संस्थाओं की आवश्यकता को निरूपित करता है। अतः डी.एल.एड. प्रशिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य व अवधि का पालन करना प्रशिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता का सूचक है।

निष्कर्ष

1. 94.45 प्रतिशत प्राचार्यो ने प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष उचित माना है जबकि 05.55 प्रतिशत प्राचायों ने इसे अस्वीकार किया है।
2. 77.78 प्रतिशत प्राचार्यो ने डी.एल.एड. का प्रशिक्षण शुल्क को उचित माना है जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचायों ने इसे अस्वीकार किया है।
3. 94.45 प्रतिशत प्राचार्यो ने प्रशिक्षण अवधि में 200 कार्य दिवस पर को उचित मानते है जबकि 5.55 प्रतिशत प्राचार्य इस सुविधाजनक नही मानते है।
4. 88.89 प्रतिशत प्राचार्यो ने स्वीकार किया है कि प्रशिक्षण में प्रति सप्ताह 36 घण्टे कार्य का लक्ष्य पूरा किया जाता है जबकि 11.11 प्रतिशत प्राचार्य इसे नहीं मानते है।
5. 77.78 प्रतिशत प्राचार्यो छात्राध्यापको की उपस्थिति स्वीकारते है जबकि 22.22 प्रतिशत प्राचार्य छात्राध्यापको की उपस्थिति से संतुष्ट नहीं हैं।
6. डी.एल.एड. के नये पाठ्यक्रम को 88.88 प्रतिशत प्राचार्य सक्षम मानते है जबकि 11.12 प्रतिशत प्राचार्य इसे सक्षम नही मानते।
7. 61.11 प्रतिशत प्राचार्यो ने समुदाय के सक्रिय सहयोग को माना है। 38.89 प्रतिशत प्राचार्य समुदाय के सहयोग नही मिलने की बात करते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

चन्द्रशेखर, के. (2000)– एन इवैलूयेटिव स्टडी आफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम इन आन्ध्रप्रदेश, पी–एच.डी. थिसिस, एजुकेशन श्री वेंकेटेश्वरा विश्वविद्यालय, तिरूपति।

चन्द्रशेखर, के. (2007)– ''टीचर एजुकेशन्स पर्सेप्सन्स आफ डाईट्स फेसीलिटीज एण्ड दीयर रिलेसन्स टू सर्टेन पर्सनल एण्ड डिमोग्राफिक वैरियेबल्स'' पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन हरिनगर रेसकोर्स बडौदा, वाल्यूम 23 (2), अप्रैल 2017 पृष्ठ : 92–104।

डेलर्स, जे. एट. आल (1996)– ''क्वालिटी टीचर्स, लर्निंगः दी टेजर विदिन' रिपोर्ट टु यूनेस्को ऑफ दी इण्टरनेशनल कमीशन आन एजूकेशन फार दी ट्वेन्टी फर्स्ट सेन्चुरी, पृष्ठ–146 पेरिस, यूनेस्को, कोटेड इन दी इण्डियन्स जर्नल फार टीचर एजूकेशन, एन.सी.टी.ई., नई दिल्ली, वाल्यूम (1) , अगस्त 1998।

दास,आर.सी.एण्ड जंगीरा, एन.के. (2004)– 'ए ट्रेण्ड रिपोर्ट, टीचर एजुकेशन' 'थर्ड सर्वे ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन', नई दिल्ली,एन.सी.ई.आर.टी. पृष्ठ 782–789।

दीपा कृष्णा एण्ड सरोज आनन्द (2006)– ष्गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण–जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिकाष् अन्वेषिका 3 (2) दिसंबर 2006, पृष्ठ 75 से 80।

गव्हर्नमेंट आफ इंडिया (1989)– गाइडेन्स आफ डाइट नई दिल्ली, मिनीस्टरी आफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेन्ट, डिपार्टमेन्ट आफ एजूकेशन कोटेड इन पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, वाल्यूम 23 (2), अप्रैल 2007।

गायत्री, ए. (1996)– एन इनवेस्टीगेशन इन्टू द परसेप्सन आफ स्टूडेन्ट टीचर्स आन देयर टीचर ट्रेनिंग, अनपब्लिस्ड एम.एड. डिजरटेशन, एस.व्ही. विश्वविद्यालय, तिरूपति।

गौड़, यशवन्ती (2013)– ''जयपुर जिले के बी. एस. टी. सी. संस्थाओं में शैक्षिक गुणवत्ता हेतु किए जा रहे प्रयास''– एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, पी–एच.डी. थिसीस एजू. वनस्थली, राजस्थान।

सिंह, विनीता (2009–10)– '' छत्तीसगढ़ राज्य की जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की सुविधाओं के विषय में प्रारंभिक शिक्षक–प्रशिक्षको का प्रत्यक्ष बोधः उनकी आयु, लिंग, शैक्षिक योग्यता तथा अध्यापन अनुभव के विशेष सन्दर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन रिसर्च थीसिस, बिलासपुर (छ.ग.)।